पर उनको मुफ्त किताबें भी दी जाती हैं। हम लोगों का यह टारगेट है कि लड़के और लड़कियों के बीच जो यह अंतर है, इसको कम किया जाए और लड़के और लड़कियां बराबर की शिक्षा ले सकें, इसका इंजताम हम लोग कर रहे हैं।

Financial package for sick SSIs

*122. PROF. M.M. AGARWAL: Will the Minister of SMALL SCALE INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government have proposed to give any financial package for revival of sick small scale industries in the country;

(b) if so, the amount allocated for this purpose by Government during the current year; and

(c) the funds released by Government so far?

THE MINISTER OF SMALL SCALE INDUSTRIES (SHRI MAHAVIR PRASAD): (a) to (c) A statement is placed on the Table of the House.

Statement

(a) The Central Government does not provide any financial assistance for rehabilitation of sick Small Scale Industries (SSIs).

However, financial assistance, by way of debt restructuring, including fresh loans, etc., for the rehabilitation of sick SSI is provided by the primary lending institutions (PLI), including the commercial banks. For this purpose, the Reserve Bank of India (RBI) has issued guidelines to banks from time to time on detection of sickness in SSI at an early stage and taking remedial measures and for rehabilitation of sick SSI units identified as potentially viable.

After the detailed guidelines of January 2002, the RBI has issued fresh guidelines on 8th September 2005, based on the "Policy Package" for Stepping up Credit to Small and Medium Enterprises (SMEs) announced by the Central Government on 10th August, 2005. These guidelines related, *inter alia,* to viability criteria, prudential norms for restructured accounts, provision of additional finance, time frame for working out the restructuring package and its implementation, etc.

The banks have also been advised by the RBI to review the progress in rehabilitation and restructuring of SME accounts on a quarterly basis. The State Level Inter-Institutional Committee (SLIIC), set up in each State

under the convenorship of the RBI representative, has also been advised to monitor, *inter alia,* the implementation of these guidelines.

(b) and (c) In view of the foregoing, do not arise.

प्रो॰ एम॰ एम॰ अग्रवाल: आदरणीय सभापति जी, मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में 1,18,000 स्मॉल स्केल इकाइयां हैं, जिनमें से 8,900 इकाइयां बिल्कुल बंद पड़ी हैं। उनको खालने के लिए क्या मंत्री जी ने कोई नया पैकेज बनाया है या उनके लिए आप कोई नया तरीका निकाल रहे हैं, जिससे वे revive हो जाएं और मार्केट में दोबारा compete कर सकें।

श्री महावीर प्रसाद: आदरणीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, मैंने इसके पहले भी उत्तर दिया था और आज जो इन्होंने कहा कि रुग्ण इकाइयां हैं, तो हमारी सूचना के अनुसार 1999 में 3,06,221 रुग्ण इकाइयां थीं, लेकिन वर्ष 2004 में इनकी संख्या 1.3 लाख रह गई है। सरकार, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों के आधार पर इसके लिए विशेष प्रयत्न कर रही है कि हम रुग्ण इकाइयों को कम से कम करें और उनकी संख्या हम सदन के सामने रखना चाहते हैं।

श्री सभापति: सदन के सामने रखने से क्या होगा?

श्री महावीर प्रसाद: सर, हम इनकी संख्या माननीय सदस्य को बताएंगे। हमने लघु उद्योग रुग्णता को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। मुझे आपका संरक्षण मिलना चाहिए।

श्री सभापति: पूरा संरक्षण है।

श्री महावीर प्रसाद: ये उपाय हैं:—

(i) RBI ने आरंभिक चरण में रुग्णता की पहचान और उपचारात्मक उपाय करने और संभावित जीवन के रूप में पहचानी गई रुग्ण लघु इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए जनवरी, 2002 में बैंकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

(ii) RBI ने 8 सितंबर, 2005 को ऋण पुनर्व्यवस्था तंत्र से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि सभी पात्र लघु एवं मध्यम लघु उद्योगों को ऋण की पुनर्व्यवस्था सुगम की जा सके।

(iii) RBI प्रतिनिधि के संयोजन के तहत प्रत्येक राज्य में इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य-स्तरीय अंतर-संस्थानिक समिति की व्यवस्था भी की गई है।

(iv) आर॰बी॰आई॰ ने लघु एवं मध्यम उद्यम लेखों के लिए एक बार के निपटान, ओ॰टी॰एस॰ की योजना पर 3 सितम्बर, 2005 को सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

(v) रुग्ण लघु एवं मध्यम इकाइयों के पुनर्वास, पुनर्व्यवस्था ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: यह सबके पास आ गया ...(**व्यवधान**)...

श्री महावीर प्रसाद: इसकी व्यवस्था करने के लिए ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है। आपका जवाब सबके पास आ गया। श्री वेदप्रकाश गोयल।

प्रो॰ एम॰ एम॰ अग्रवाल: सर, मेरा सेकंड सप्लीमेंटरी है।

श्री सभापति: सेकंड सप्लीमेंटरी। अब आप क्या करोगे सेकंड सप्लीमेंटरी पूछ कर ... (**व्यवधान**)... आप सेकंड सप्लीमेंटरी से क्या एचीव करोगे ...(**व्यवधान**)... आप आराम करो।

प्रो॰ एम॰ एम॰ अग्रवाल: सर, पूछ लेने दीजिए।

श्री सभापति: ठीक है। आप बैठ जाइए। Please take your seat. ...(*Interruptions*)... Don't disturb. ...(*Interruptions*)... ठीक है। आप इनको बोलने दीजिए। अगर इन्हें कुछ एचीवमेंट हो जाए, तो दूसरा सप्लीमेंटरी कर सकते हैं।

प्रो॰ एम॰ एम॰ अग्रवाल: सर, स्माल स्केल इंडस्ट्री से आज अभी तक 38 परसेंट हमारा एक्सपोर्ट होता है। अगर इसमें नई टेक्नोलॉजी लाई जाए और नई-नई ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: ये सब बातें तो पैकेज में आ ही जाएंगी ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ एम॰ एम॰ अग्रवाल: पैकेज में कहां आईं अभी?

श्री सभापति: पैकेज में आएंगी।

प्रो॰ एम॰ एम॰ अग्रवाल: मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे कोई नई टेक्नोलॉजी लाने का प्रयत्न कर रहे हैं?

श्री सभापति: वह इसमें नहीं आएगा।

SHRI VEDPRAKASH P. GOYAL: Sir, the answer does not convey anything specific, it only talks of guidelines. The first part of my question is this. What is the loss of revenue in export in net terms, that is, exports minus imports due to the closure of the small-scale industries, which provide largest employment in the agencies? Large industries do not provide much employment.

The second part of my question is this. There are six steps, which can be monitored. Even at the State level, the Central Government has got some role to play. What is the role of a separate Central Ministry for

the Small Scale and Medium scale industry? If you could give some specific answer, I will be grateful.

श्री महावीर प्रसाद: महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस सन्दर्भ में उन्होंने निर्यात की जो बात पूछी है, मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि लघु उद्योग की हिस्सेदारी सम्पूर्ण उद्योग जगत में आज 39 प्रतिशत है और निर्यात के सन्दर्भ में हमारी हिस्सेदारी 34 प्रतिशत है। मैं आपके संज्ञान में यह लाना चाहता हूं एवं आपके माध्यम से माननीय सदस्य महोदय को बताना चाहता हूं कि ये लघु उद्योग, कुछ उद्योगों को छोड़कर, जैसे रक्षा विभाग में या एटोमिक एनर्जी में कुछ उद्योग हैं, जो केन्द्र सरकार के खाते में आते हैं, लेकिन सही में लघु उद्योग राज्य सरकार का विषय है, जिसमें राज्य सरकार को लघु उद्योगों को जीवन देने के लिए? जैसे उदाहरण के लिए वहां पर सड़क की व्यवस्था करना ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: अब आप उदाहरण मत दीजिए। सब समझ गए।

श्री महावीर प्रसाद: पानी की व्यवस्था करना। मैंने कह दिया कि इसमें नीति राज्य सरकार के द्वारा ...(व्यवधान)... श्रीमन्, धैर्य रखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि राज्य स्तर पर एक समिति बनाई गई है। उसकी छान-बीन करने के लिए एक समिति वहां के उद्योग सचिव की अध्यक्षता में है और उस समिति के आधार पर हम बन्द इकाइयों की और रुग्ण इकाइयों की बैंकों के द्वारा छान-बीन किया करते है।

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister himself admits that small-scale industries contribute more for employment, and also for 39 per cent of the exports in this country. It also brings a lot of revenue to the Government.

MR. CHAIRMAN: Please come to the question. There is no need for any background.

SHRI V. NARAYANASAMY: I would like to know from the hon. Minister about the concessions that have been provided in the name of electricity subsidy. Also, when they got the raw material, some kind of a concession by way of tax rebate was given, that has been withdrawn. Now I would like to know whether in the package he would be able to prevail upon the State Government by giving those concessions.

MR. CHAIRMAN: If you can prevail upon the State Government, then say something.

श्री महावीर प्रसाद: महोदय, राज्य सरकारों के बिजली के विषय में और जो सुविधाएं लघु उद्योगों को वापस नहीं दी गयी हैं, उसके विषय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यह राज्यों का मामला है।

DR. K. MALAISAMY: Sir, as the hon. Chairman and the entire House are fully aware, the small-scale industry sector is a very vital sector and plays a very significant role in terms of employment, in terms of production, in terms of export, etc. etc. Sir, the fact remains that in spite of all these measures said by the Minister, the small-scale industries are becoming sick. In the statement it has been said that the revised guidelines have been issued. Sir, my specific question is this: After issuing these revised guidelines, how many sick industries have been revived, in terms of percentage or in terms of numbers? I would like to know whether it is only on paper, or, it is the ground reality.

श्री महावीर प्रसाद: आदरणीय महोदय, मैंने अभी-अभी बताया था कि 2004 में, हमारे पास जो बिल्कुल लेटेस्ट सूचना है, उस के अनुसार 1.38 लाख रुग्ण इकाइयां अभी हैं। उसके बाद अभी तक आंकड़ा नहीं आया है। ...**(व्यवधान)**... महोदय, रिजर्व बैंक के द्वारा जितने हमारे बैंक्स होते हैं और जो ऋण देते हैं, ये सूचनाएं उन बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक को आती है। फिर रिजर्व बैंक हमारे मंत्रालय को सूचना देती है। इस तरह से मैंने अभी बताया कि 1 लाख 38 हजार रुग्ण इकाइयां हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए, प्लीज।...**(व्यवधान)**... Let it remain. ..(*Interruptions*)... आप बैठे-बैठे बोलेंगे तो मुझे खड़े होकर बोलना पड़ेगा। श्री मोती लाल वोरा।

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति महोदय, मैं पहले तो माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जहां 3 लाख रुग्ण इकाइयां थीं, वे अब घटकर 1 लाख 38 हजार रह गयी हैं। माननीय सभापति महोदयां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद रुग्ण इकाइयों को बैंक में कठिनाइयां आती हैं, क्या उन कठिनाइयों को दूर करने की दिशा में आपने कोई कदम उठाए हैं क्योंकि जो रुग्ण इकाइयां हैं, उन को बैंक से फाइनेंस करना हो या उन की वाएबिलिटी के विषय में हो, उन्हें वहां जाना पड़ता है? दूसरे, मैं जानना चाहूंगा कि इन इकाइयों में कितने लाख लोग काम कर रहे हैं क्योंकि बड़ी इकाइयों में रोजगार बहुत कम मिलता है और इन छोटी इकाइयों में ही अधिक रोजगार मिलने की संभावना रहती है? तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी देंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश के बाद बैंकों द्वारा जिस प्रकार की ढिलाई, उन इकाइयों के रिवाइवल में होती है, तो उस विषय में आप कोई स्पष्ट निर्देश देंगे?

श्री महावीर प्रसाद: सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 10 अगस्त, 2005 को फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो घोषणा की गयी थी, उस आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न बैंक्स को दिशा-निर्देश दिए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वह पूरा पढ़कर बता दूं?

श्री सभापति: नहीं-नहीं बैठ जाइए। Please take your seat.

श्री मोती लाल वोरा: कितने लोग काम करते हैं?

श्री महावीर प्रसाद: महोदय, लघु उद्योग में पी०एम०आर०वाई० का अलग से आंकड़ा आता है, आर०इ०जी०पी० का अलग से आता है और अन्य लघु उद्योग का अलग आता है, इसलिए मैं आप को अलग से लिखित में भेज दूंगा कि संपूर्ण लघु उद्योगों में कितने लोग काम कर रहे हैं।

यू० एस० ओ० निधि का उपयोग

*123. **श्री राम जेठमलानी:**††
श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड कर के रूप में वसूल किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष औसतन कितनी धनराशि एकत्र की गई;

(ग) प्राप्त धनराशि में से औसतन कितनी धनराशि बांटी गई; और

(घ) बांटी गई धनराशि के उपयोग का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है?

विवरण

(क) इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, वायस मेल, ई-मेल आदि जैसे मूल्यवर्धित सेवा प्रदाताओं को छोड़कर सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 5% की दर से सार्वभौमिक सेवा लेवी (यू०एस०एल०) का भुगतान कर रहे हैं।

(ख) सार्वभौमिक सेवा सहायता नीति 1.4.2002 से लागू हुई थी। वर्ष 2002-03 से 2004-05 की अवधि के दौरान वार्षिक रूप से औसतन 2418.19 करोड़ रुपए की राशि वसूल की गई थी।

(ग) वर्ष 2002-03 से 2004-05 की अवधि के दौरान वार्षिक रूप से औसतन 604.86 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई थी। वर्ष 2005-06 के दौरान, 13.02.2006 तक 1,401.71 करोड़ रुपए संवितरित किए जा चुके हैं।

---

††सभा में यह प्रश्न श्री राम जेठमलानी द्वारा पूछा गया।